शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 45 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 31–7 नवम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

"पन्द्रह साल नड्डा ने जलील किया है"

कृपाल परमार का आरोप

शर्मनाक हार की ओर बढ़ रही है स्थितियां
सभी मंत्री संकट में
मुख्यमंत्री को कांग्रेसियों से मांगना पड़ रहा है सहयोग

शिमला/शैल। भाजपा के बागियों को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को उन्हें फोन करने पड़े हैं। यह प्रधानमंत्री की पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार से हुये संवाद के वायरल होने से बाहर आ गयी है। मोदी कृपाल परमार को फोन पर चुनाव से हट जाने का अनुरोध करते हैं और परमार ने दो दिन लेट हो गये कि बात करके यह भी साफ सुना दिया की नड्डा ने उन्हें पन्द्रह साल जलील किया है। नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल के बिलासपुर से आते हैं और बिलासपुर में ही कुछ बगियों ने उन्हें मिलने तक से इन्कार कर दिया यह भी सामने आ गया है। हिमाचल को छोड़कर

उन सभी भाजपा शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ या होने के प्रयास हुये जहां चुनाव होने थे। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हो पाया। कुछ मंत्रियों की छुट्टी करने कुछ के विभाग बदले जाने का प्रचार गोदी मीडिया के माध्यम से लगातार करवाया जाता रहा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए आज भाजपा के करीब दो दर्जन बागी चुनाव लड़ रहे हैं। आज धूमल को जिस तरह हाशिये पर धकेल दिया गया उसकी पीड़ा अनुराग ठाकुर के आंसुओं से सार्वजनिक हो चुकी है। महेश्वर सिंह के बेटे ने महेश्वर को टिकट दिये जाने से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। नड्डा को यह जानकारी होने के बाद भी महेश्वर सिंह को दिल्ली बुलाया गया और टिकट दिया गया। इस टिकट को अन्तिम दिन बेटे के चुनाव से न हटने के दण्ड के रूप में बदल दिया गया। महेश्वर का दर्द उनके आंसूओं में सार्वजनिक हो गया। क्या महेश्वर को टिकट देने से पहले बेटे को चुनाव से हटाने की शर्त रखी गयी थी यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। जब निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा को पार्टी में शामिल किया गया था तब यह आरोप लगा कि इन्हें लाने से पहले धूमल जैसे वरिष्ठ नेताओं से राय नहीं ली गयी है। बल्कि संबंधित मण्डल तक को विश्वास में नहीं लिया गया। इसी पर उभरी नाराजगी लखविंदर राणा और पवन काजल के शामिल होने तक जारी रही। फिर हर्ष महाजन और विजय सिंह मनकोटिया को शामिल करने में क्या शान्ता कुमार प्रेम कुमार धूमल से राय ली गयी थी शायद नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल नड्डा और जयराम ही जिम्मेदार हैं।

हिमाचल में यह स्थिति लगभग पहले दिन से ही बन गयी थी। इसी का परिणाम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव इतने प्रचण्ड मार्जन से जीतने के बाद भाजपा ने दो नगर निगम के चुनाव हारे फिर तीन विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव। बीस विधानसभा चुनाव क्षेत्र इससे प्रभावित हुये। जुब्बल – कोटखाई जो 2017 में भाजपा के पास थी वहां भाजपा जमानत नहीं बचा पायी। जबकि कांग्रेस ने अर्की और फतेहपुर पर अपना कब्जा बरकरार रखा। यहां पर 2017 के चुनाव के इस तथ्य पर भी नजर डालना आवश्यक हो जाता है कि इस चुनाव के समय भाजपा में नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं थे। बागियों की कोई समस्या नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ कोई प्रश्न मुखर नहीं थे। तब भी उस समय भाजपा की पन्द्रह सीटों पर जीत दो हजार से कम के अन्तर से हुई थी। दस सीटों पर निर्दलीयों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। आज यह पच्चीस सीटें सीधे भाजपा के हाथ से निकलती नजर आ रही है। क्योंकि जब प्रधानमन्त्री को बागियों को फोन करने की नौबत आ जाये और उसका कोई असर तक न हो तो संगठन के भीतर की स्थिति सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती है। आज भाजपा इन सारी स्थितियों से बुरी तरह घिरी हुई है। 2017 के चुनाव के दौरान मण्डी की एक जनसभा में हिमाचली कर्मचारियों को नामत: यह आश्वासन दिया था कि जो काला धन वापस आने वाला है उसमें से कुछ हिस्सा हिमाचली कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री के ब्यान का यह वीडियो चुनावों में वायरल हो चुका है। बिलासपुर में ड्रोन ज्ञान और चम्बा में रेल पहुंचने की उपलब्धियां गिनाता केंद्रीय नेतृत्व भी आज प्रदेश में प्रसांगिक हो गया है। क्योंकि उसके दिये हुये 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग आज सैद्धांतिक स्वीकृति से आगे नहीं बढ़े हैं।

आज महंगाई और बेरोजगारी के आगे धारा 370 और तीन तलाक बहुत छोटे हो गये हैं। 2014 से आज तक लगातार आम आदमी के जमा पर कम होता गया ब्याज और कर्ज के महंगा होने तथा डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होते जाने के सच के सामने राम मंदिर का निर्माण भी इससे राहत नहीं दिलवा पाता है। आज सरकार की वित्तीय स्थिति उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गयी है कि वह दिसम्बर के बाद गरीबों को सस्ता राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं रह गयी है। क्योंकि बैंकों से जो लाखों करोड़ कर्ज दिलवाया गया था वह आज तक वापस नहीं आ पाया है। ऊपर से आरबीआई द्वारा जारी नौ लाख करोड़ के नोट कहीं गायब हो गये हैं जिनकी विधिवत जांच तक नहीं हो पायी है। यह सारे घाटे आम आदमी की जेब से पूरे करने के लिये हर सेवा को लगातार महंगा किया जा रहा है। यह सारे सच अब आम आदमी को समझ आ चुके हैं। इसी का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री को ही करीब एक दर्जन चुनाव सभाएं करने के साथ ही बागियों को मनाने के लिये स्वयं फोन करने पड़ रहे हैं। इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा को इन चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने की आशंका डराने लग गयी है। क्योंकि संघ पार्टी आईबी और सीआईडी किसी के भी सर्वेक्षण में 15 से 20 सीटों से ज्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ा है।

भाजपा की यह स्थिति इसलिये हुई है क्योंकि जो कुछ विज्ञापनों में विज्ञापित किया जा रहा है वह जमीन पर देखने में मिल नहीं रहा है। स्कूलों में बच्चों को वर्दियां नहीं दी जा सकी हैं। मिड डे मील के पैसे अध्यापकों को अपनी जेब से देने पड़े हैं। घटिया वर्दी सप्लाई करने के लिये जिन फर्मो पर कांग्रेस सरकार ने करोड़ों का जुर्माना लगाया था इस सरकार ने उसे माफ करके फर्मो को अभयदान दे दिया। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय से अपील दायर करने की अनुशंसा स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फाइल पर कर रखी है। जिस पर पांच वर्षो में अमल नहीं हो पाया। क्योंकि प्रशासन ने विकास की सीमा ओक ओवर के दो मंजिला मकान में लिफ्ट लगने से आगे बढ़ने ही नहीं दी। इससे मुख्यमंत्री की प्रशासन पर पकड़ इतनी कमजोर पड़ गयी कि सवैधानिक पदों पर बैठे लोग उद्योगपतियों के लिये आयोजित इन्वैस्टर मीट में शिरकत रहे और सरकार में किसी का भी इसका संज्ञान लेने का साहस तक नहीं हुआ। ऐसी स्थितियों से जो सन्देश आम आदमी तक पहुंचा वह आज गले पड़ गया है। यह माना गया है कि इस प्रशासन में सब को लूट की बराबर छूट है। शर्त यह थी कि लूट की जिम्मेदारी किसी बड़े पर नहीं आनी चाहिये।

इसी का परिणाम है कि चुनाव में मुख्यमंत्री को कांग्रेसियों से सहयोग की अपील करनी पड़ रही है। नड्डा के सहयोग से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक यह अन्दर की कहानी नहीं पहुंचने दी गयी। आम आदमी और पार्टी के जिम्मेदार लोगों तथा सरकार के बीच संवाद का ऐसा संकट खड़ा हुआ जिसने आज प्रधानमंत्री तक की बात न सुनने के सार्वजनिक हालात पैदा कर दिये। क्या इस परिदृश्य में हो रहे चुनाव में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार किसी भी गणित से पुन: सत्ता में वापसी की सोच सकती है।

भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देशहित में अनुशासन और स्वदेशी की भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण को जीवन

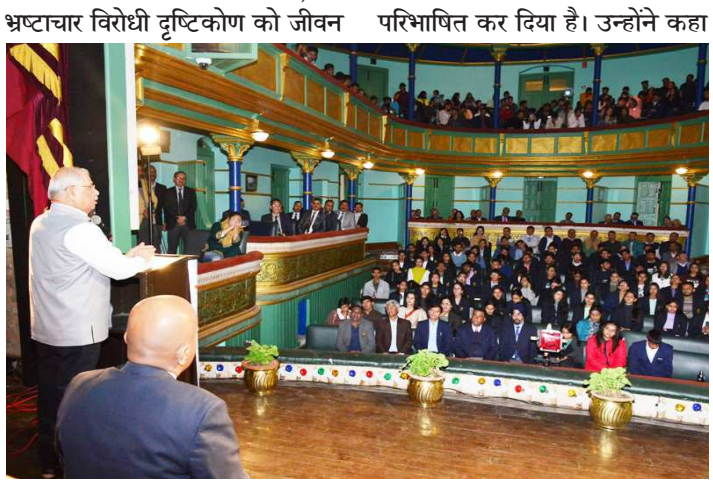

शैली का हिस्सा बनाना चाहिए।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राज्य सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा 31 अक्तूबर से 6 नवंबर, 2022 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने राज्य सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सुझाव और उपाय केवल यहीं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हें व्यावहारिक तौर पर उपयोग में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए और गलत प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है जिसके लिए सभी को बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए।

आर्लेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार मानवीय स्वभाव से आता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमने अपने सार्वजनिक और निजी जीवन से धर्म को अलग कर दिया, हम भ्रष्ट होने लगते हैं क्योंकि हमने धर्म को गलत परिभाषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह जीवन और आचरण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धर्म हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने धर्म को जीवन का हिस्सा बनाने पर बल दिया।

राज्यपाल ने समाज में तेजी से फैल रहे भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे ऊपरी स्तर पर फैलने से रोकने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि आचरण, सोच, स्वभाव, समय से भी संबंधित है। ऐसे में हमें अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुशासन दूसरों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विशेष रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को अपने अच्छे आचरण से विभागीय छवि को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 'अमृत काल' में हमें आगे बढ़ कर भ्रष्टाचार मुद्र भारत को लक्ष्य मान कर कार्य करने की आवश्यकता है।

आर्लेकर ने युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और स्वदेशी अपना कर हम विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह सोच भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य सतर्कता विभाग की वैबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया।

इससे पूर्व, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक सतवंत अटवाल ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए ब्यूरो द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने विद्यालय स्तर तक आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो शिव कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी क्षेत्र अंजुम आरा ने इस अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नैक टीम ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दौरे पर आई राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

(नैक) की टीम ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार भेंट की।

उन्होंने राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और इसके पश्चात राजभवन परिसर का भी दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित भी किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जयन्ती पर बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुरु नानक देव जी की जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिक्खों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का संदेश हमें पवित्र, संवदेनशील जीवन तथा समावेशी समाज की राह दिखाता है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षाओं ने हमें करूणामय, संवदेनशील और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया है।

वित्त एवं लेखा सेवाएं के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवाएं के 20 प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। ये प्रशिक्षु अधिकारी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान (हिप्पा) में लगभग 10 महीनों की अवधि का से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने इन अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि वित्त अधिकारियों का वित्तीय संबंधी मामलों से निपटने में महत्त्वपूर्ण योगदान है

जिसके लिए उन्हें नई तकनीक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को उनके नए उपक्रमों के लिए बधाई दी और प्रतिबद्धता, ईमानदारी तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा।

आर्लेकर ने कहा कि विकास प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस सुंदर पर्वतीय राज्य में रहने का अवसर मिला है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वस्थ वातावरण के लिए भी जाना जाता है। राज्यपाल ने कहा, 'हमें अपनी संभावनाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए और राजस्व स्रोतों को सक्रिय करना चाहिए जिसके लिए युवा सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।'

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक, हिप्पा ज्योति राणा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि प्रशिक्षण को दो भागों में किया जाएगा जिसके दोनों भागों में पांच-पांच महीनों का प्रशिक्षण शामिल होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरांत प्रशिक्षुओं को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और दोनों भागों की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही वित्त विभाग द्वारा किसी सरकारी विभाग/ राज्य के संस्थानों में बतौर अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त अधिकारियों को विभागों/ संस्थानों में विभिन्न कार्य जिनमें वित्तीय संबंधी मामले, महालेखाकार कार्यालय से संबंधित वित्तीय मामले, नीति और नियमों से संबंधित मामले, विभागीय संबंधी मामले तथा संबंधित विभागों के मुखिया द्वारा दिए गए कार्य शामिल होंगे।

पाठयक्रम निदेशक, विकास गुप्ता और संयुक्त निदेशक हिप्पा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किया नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान

शिमला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विभिन्न सामाजिक संगठनों से सामाजिक विसंगतियों व नशे जैसी

बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि इस विषय में वह स्वयं भी सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में जाकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि इस बुराई के खिलाफ ठोस प्रयास किए जा सकें। उन्होंने यह बात राजभवन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत में कही।

उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशे के कारणों व दुष्प्रभावों को हम सभी भलीभांति जानते हैं लेकिन यदि हम सामाजिक दायित्व नहीं निभाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी में भटकाव संभव है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और समाज को दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए अनेक कानून हैं लेकिन फिर भी यह बुराई समाज में व्याप्त है तथा जैसे-जैसे हम समाज को जागरूक करेंगे यह बुराई स्वत: दूर होती चली जाएगी। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने का प्रयास होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ वे स्वयं शिक्षण संस्थानों में अगले सत्र से जागरूकता कार्यक्रम आरम्भ करेंगे जिनमें सभी सामाजिक संगठनों का भी योगदान लिया जाएगा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

हिमाचल के विकास की राह को तेजी देने के लिए एक स्थिर सरकार जरूरी:प्रधानमंत्री

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सोलन में एक जनसभा को संबोधित किया और खुद को सोलन का डबल कर्जदार बताया।

पीएम ने कहा कि सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि हिमाचल में फिर डबल इंजन सरकार आएगी। हिमाचल के विकास की राह को तेजी देने के लिए एक स्थिर सरकार जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सोलन में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला साथ ही पीएम ने खुद को सोलन का डबल कर्जदार बताया। पीएम ने कहा कि सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि हिमाचल में फिर डबल इंजन सरकार आएगी। पीएम ने कहा कि सोलन ने मुझे खूब खिलाया भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है। इसलिए मैं सोलन का डबल कर्जदार हूं, इसलिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। पीएम ने कहा कि मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा लगाव बना रहता है। हिमाचल के लोगों का जो स्नेह है, मैं इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता। लेकिन हिमाचल का विकास कर, हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूं।

पीएम ने कहा कि हिमाचल के विकास की राह को तेजी देने के लिए एक स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस बात को हिमाचल के युवा, माताएं-बहनें और बड़े-बुजुर्ग अच्छी तरह से जानते हैं। पीएम ने कहा कि हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्षो के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थ तत्व और समूह पैदा हो गए हैं जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहते, भारत में स्थिर सरकार नहीं देखना चाहते। देश के छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं।

पीएम ने कहा कि उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य हैं, जिन्होंने अब स्थिर सरकार की ओर अपना रुख कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भी वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, वहां भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई, जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद, काबू में आये, नार्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई।

पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा- ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं, हिमाचल को ऐसे स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है।

सी.बी. बरोवालिया ने हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त की शपथ ग्रहण की

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया (सेवानिवृत्त) ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की।

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य सचिव आर. डी.धीमान ने शपथ ग्रहण कार्यवाही का संचालन किया तथा राज्यपाल की ओर से जारी वॉरेंट ऑफ अप्वाइंटमेंट पढ़ा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ पत्र पर लोकायुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर, जस्टिस एल.एस. पांटा, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त, पूर्व न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस:शाह

शिमला/शैल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प रैली में भाग लिया उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज के लिए प्रचार भी किया।

उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप में उपस्थित रहे।

अमित शाह ने कहा की कांग्रेस के पास मां बेटे के अलावा कुछ बचा नहीं है और हिमाचल में भी कांग्रेस के पास केवल मां बेटा ही रह गए हैं।

कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकती इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण सामने है पिछले 20 वर्ष में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है पर यहां विकास नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भारत में पिछले 60 वर्षो में नहीं कर पाई वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षो में कर दिखाया।

भारत में किसी को भी भरोसा नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा पर मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने यह यह साबित कर दिया है और आज राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है।

हिमाचल वासियों को 2024 की राम मंदिर की टिकटे बुक कर लेनी चाहिए क्योंकि 2024 में एक गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा ।

कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व पटल पर मजबूत बनाया आज केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बना कर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है।

अमित शाह ने कहा की कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं पर मैं राहुल बाबा से पूछता हूं कि वह हिमाचल तो नहीं आएंगे पर भारत में जो पदयात्रा चल रही है वहीं से बता दे कि उन्होंने भारत और हिमाचल के विकास के लिए क्या किया।

आज भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में पांचवें स्तर पर आ गया है पर आज से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में वह 11वे स्थान से कभी ऊपर नहीं आया।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कुशल राजनीतिज्ञ है आज देश की सीमा और सेना में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता कांग्रेस के समय देश में आलिया, जमालिया सब घुस जाते थे, भारत में दो सरकारों का फर्क साफ है और जनता सब जानती है।

दुनिया को पता है कि देश का प्रधानमंत्री अब कोई मोनी बाबा नहीं है परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।

विधान सभा चुनावों में मतदान के लिए 12 नवंबर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत 12 नवंबर, 2022 (शनिवार) को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 12 नवंबर, 2022 को मतदान होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों, बोर्डो, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा जो नैगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।

राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा ताकि वे अपने विधान सभा क्षेत्र/स्थान पर जाकर मतदान कर सकें। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी से मतदान से संबंधित निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मतदान से दो दिन पूर्व और मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 12 नवंबर, 2022 (शनिवार) को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस पर 8 दिसंबर, 2022 (वीरवार) को ड्राई डे घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 10 नवंबर, 2022 (वीरवार) सायं 5 बजे से 12 नवंबर, 2022 (शनिवार) सायं 5 बजे तक तथा मतगणना दिवस 8 दिसंबर (वीरवार) 2022 को ड्राई दिवस घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों एवं वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाओं तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एक्ट-2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट-1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा।

उन्होंने कहा कि इन दिनों और इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मादक द्रव्य, मद्यपेय की बिक्री तथा होटल, दुकानों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य स्थानों में किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आबकारी नियमों के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले परिसरों में लोगों द्वारा शराब के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा तथा नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कारवाई अमल में लाई जाएगी।

आयुक्त ने कहा कि संबंधित जिलों के आबकारी कलेक्टर, राज्य कर एवं आबकारी उप-आयुक्त/ सहायक आयुक्त तथा राज्य कर एवं आबकारी (उड़न दस्तों) के संयुक्त आयुक्त को अपने संबंधित क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने संबंधित तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

प्राथमिक सहायता उपचार प्रशिक्षण शिविर आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा, शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी शिमला द्वारा प्राथमिक सहायता उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन से बतौर प्राथमिक सहायता प्रशिक्षक प्रवीण महाजन व् हिमाचल प्रदेश की सभी ज़िला रेडक्रॉस शाखाओं से 29 (चालक/ स्वयंसेवक) प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे। उन्होने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी शिमला द्वारा एम्बुलेंस के चालकों व् रेडक्रॉस स्वयंसेवकों को तीन दिवसीय प्राथमिक सहायता उपचार प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में लोगो की सहायता कर सकें। प्राथमिक सहायता प्रशिक्षक प्रवीण महाजन द्वारा प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें प्राथमिक सहायता के तकनीक, मानव शरीर की सरंचना, जलना तथा झुलसना, विषक्ता, काटना एवं डंक, हड्डियों की चोट, घाव एवं रक्त बहाव, ड्रेसिंग व् पटियाँ आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक, उसके जीवन को बचाने के लिए उपयुक्त सहायता कैसे की जा सकती है तथा कैसे सी.पी.आर. दी जा सकती है तथा अंग-दान करना क्यों आवश्यक है के बारे विस्तृत जानकारी दी गई। इस तीन दिवसीय प्राथमिक सहायता उपचार प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन सचिव राज्यपाल एवं महासचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस राजेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व् इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आये प्रतिभागियों का धन्यवाद किया व् कहा कि जितना भी आपने इस प्रशिक्षण शिविर में ज्ञान प्राप्त किया उसे आप अमल में लाएंगे। उन्होने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा व् प्रतिभागियों को राष्ट्रीय रेडक्रॉस कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जल्द ही सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।

हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें, हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आपका मतदान आपकी बड़ी परिक्षा है

अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं की लम्बी टीमें चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। भाजपा के पास दूसरे दलों की अपेक्षा संसाधनों की बहुतायत है इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि भाजपा को जितना भरोसा अपने संसाधनों पर है कांग्रेस को उससे ज्यादा भरोसा आम आदमी की उस पीड़ा पर है जो उसने महंगाई और बेरोजगारी के रूप में इस दौर में भोगी है। 2014 में हुये राजनीतिक बदलाव के लिये किस तरह एक आन्दोलन प्रायोजित किया गया था। किस तरह इस आन्दोलन के नायकों का चयन हुआ और किस मोड़ पर यह प्रायोजित आंदोलन एक बिखराव के साथ बन्द हुआ। यह सब इस देश ने देखा है और आज तक भोगा है। कैसे पांच वर्ष की मांग से शुरू करके उसे अगले पचास वर्ष के लिये बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है यह सब देश देख रहा है। 2014 से आज तक देश में कोई भयंकर सूखा और बाढ़ नहीं आयी है जिसके कारण अन्न का उत्पादन प्रभावित हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद आज खाद्य पदार्थो की महंगाई कैसे इतनी बढ़ गयी है यह सवाल हर किसी को लगातार कुरेद रहा है। प्रतिवर्ष दो करोड़ स्थाई नौकरियां देने का वायदा आज सेना में भी चार वर्ष की ही नौकरी देने तक कैसे पहुंच गया यह बेरोजगार युवाओं की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी देश में सरकारी नीतियों के सहारे आपदा काल में एक व्यक्ति आदाणी कैसे सबसे बड़ा अमीर बन गया इस पर सवाल तो सबके पास है परन्तु जवाब एक ही आदमी के पास है जो अपने मन के अलावा किसी की नहीं सुनता।

2014 के प्रायोजित आन्दोलन से हुये बदलाव के बाद कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच पूरी करके उनके मामले अदालतों तक पहुंचाये जा सके हैं तो शायद यह गिनती शुरू करने से पहले ही बन्द हो जायेगी। लेकिन इसके मुकाबले दूसरे दलों के कितने अपराधी और भ्रष्टाचारी भाजपा की गंगा में डुबकी लगाकर पाक साफ हो चुके हैं यह गिनती सैकड़ों से बढ़ चुकी है। पहली बार मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगा है। सीबीआई, आयकर और ईडी जैसी जांच एजैन्सियों पर राजनीतिक तोता होने का आरोप लगना अपने में ही एक बड़ा सवाल हो जाता है। यह सरकार जो शिक्षा नीति लायी है उसकी भूमिका के साथ लिखा है कि इससे हमारे बच्चों को खाड़ी के देशों में हैल्पर के रूप में रोजगार मिलने में आसानी हो जायेगी। इस पर प्रश्न होना चाहिये या सर पीटना चाहिये आप स्वयं निर्णय करें। क्योंकि इसी शिक्षा नीति में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है।

धनबल के सहारे सरकारें पलटने माननीयों की खरीद करने की जो राजनीतिक संस्कृति शुरू हो गयी है इसके परिणाम कितने भयानक होंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। ऐसे में आज जब मतदान करने की जिम्मेदारी आती है तो वर्तमान राजनीतिक संस्कृति में मेरी राय में न तो निर्दलीय को समर्थन देने और न ही नोटा का प्रयोग किये जाने की अनुमति देती है। आज वक्त की जरूरत यह बन गयी है कि राष्ट्रीय दलों में से किसी एक के पक्ष में ही मतदान किया जाये। यह मतदान राष्ट्र के भविष्य के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। जुमलों और असलियत पर परख करना आपका इम्तहान होगा।

ब्राजील में लूला डी शिल्वा की जीत के मायने

गौतम चौधरी

दुनिया का राजनीतिक भूगोल बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिकी दादागीरी का दौर समाप्ति की ओर है। इस बीच ब्राजील में एक बार फिर से समाजवादी रुझान की सरकार का आना इस बात का संकेत है कि क्रूर पूंजीवाद के दिन लद गये और मध्यममार्गी समाजवाद के इकबाल बुलंद होने वाले हैं।

ब्राजील के उदारवादी नेता बोलसोनारो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए हैं। उनकी हार पर्यावरण व कोविड के कारण बताई जा रही है। बोलसोनारो, कथित रूप से ब्राजील में फैले पचास लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जैविक संपदा, अमेजन को अपार विध्वंस से बचाने में नाकाम रहे। यही नहीं कोरोना महामारी को उन्होंने मजाक में लिया। वे बिना मास्क के खुद घूमते थे और उनके अनुयायी इस महामारी को सामान्य–सी बीमारी बता कर प्रचार करते थे। इसके कारण ब्राजील में पांच लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। इस मौत के लिए बोलसोनारो को जिम्मेदार ठहराया गया। कोविड ने ब्राजील को ग्रस लिया। यहां तक कि भारत से प्राप्त कोवेक्सिन का उपयोग भी वे ठीक से नहीं कर पाए।

नये राष्ट्रपति इग्नेशिया लूला डी शिल्वा पुराने सोशलिस्ट नेता हैं। वे जेल भी काट आये हैं और ब्राजिल में लोकतंत्र की स्थापना में बड़ी भूमिका भी निभाई है। मसलन, क्रान्तिकारी रहे हैं। सड़क के किनारे जूता पॉलिश करने से लेकर धातु कारखाने में श्रमिक तक का काम कर चुके हैं। वहीं उन्होंने श्रमिक यूनियन का नेतृत्व किया और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। लूला अपने राजनीतिक दल का नाम वर्कर्स पार्टी रखा है। फौजी तानाशाह के खिलाफ मोर्चा लिया, यातनाएं सही। लूला केवल ब्राजील के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण लैटिन अमेरिका के लिए एक नायक से कम नहीं हैं। इससे पहले भी वे ब्राजील का दो बार नेतृत्व कर चुके हैं। जब वे पहली बार देश के राष्ट्रपति बने तो कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिससे देश के आम लोगों को बेहद फायदा हुआ। आम लोगों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक बदलाव आया। देश के शिक्षा और स्वास्थ्य को लोकोपयोगी बनाया। इस बात को लेकर क्रूर पूंजीवाद का केन्द्र समझा जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील के खिलाफ हो गया। यही नहीं लूला को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की लेकिन लूला अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। लूला ब्राजील में समतामूलक समाज के निर्माण में कामयाब रहे और अमेरिकी साम्राज्यवाद से लोहा लेते रहे। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप के कारण लूला को सत्ता गवांनी पड़ी लेकिन उसकी छवि पर कोई खास प्रभास नहीं पड़ा। लूला एक बार फिर से ब्राजिल का भविष्य बनने वाले हैं।

इधार लूला के प्रतिद्वंद्वी बोल्सोनारो, दक्षिणपंथी मानसिकता के व्यक्ति हैं। घृणास्पद बातें के लिए वे बराबर चर्चा में रहे हैं। बोल्सोनारो कैथोलिक ईसाई की रुढ़िवादिता में विश्वास करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। बोलसोनारो की नजर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कद छोटा है। उनके आंकलन में अरब तथा अफ्रीकी राष्ट्र मानवता की संचित गंदगी है। ब्राजील की सेना से रिटायर बोलसोनारो सैनिक शासन की वकालत करते रहे हैं। बोल्सोनारो को ब्राजील का ड़ोनल्ड ट्रंप माना जाता है। वह नारी–द्वेषी है। यह विद्वेष उनके घर में भी दिखता है। उनके दो पुत्र हैं। तीसरी संतान बेटी है, जिसके बारे में वे सार्वजनिक मंचों से आलोचना की है। उनकी दृढ मान्यता है कि सेक्युलर गणराज्य की अवधारणा ही फिजूल है। बोलसोनारो की दृष्टि में ईश्वर सर्वोपरि है। बोलसोनारो का कहना है कि यदि अठारह वर्ष से कम का व्यक्ति बलात्कार आदि घृणित अपराध करता है तो उसे बालिग की भांति दण्ड मिले। इस पर उनकी विपक्षी सांसद तथा पूर्व मानवाधिकार मंत्री मारिया डी रोजारियो ने बोलसोनारो को रेपिस्ट कहा। महिला नेता के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोल्सोनारो ने कहा था कि मारिया तो बलात्कार के लायक भी नही है। यह मामला न्यायालय तक गया और बोलसोनारो को सजा भी मिली। बोलसोनारो का मानना है कि हिंसा शासन का अनिवार्य अंग है। एक टीवी इन्टर्व्यू में वे बोले कि ब्राजील को विकसित बनाना है तो तीस हजार लोगों को गोली से उड़ा देनी चाहिए। इसकी शुरूआत समाजवादी नेता प्रोफेसर फर्नाण्डो हेनरिख कार्डोसो से होनी चाहिए।

ब्राजिलियन ट्रंप का पटाक्षेप हो चुका है। उसके स्थान पर ब्राजील की जनता ने लूला के हाथ में अपना भविष्य सौंप दिया है। लूला ब्राजील को किस दिशा में ले जाएंगे यह तो समय बताएगा लेकिन लूला उन मुद्दों पर चुनाव जीतकर आए हैं, जो अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्रों को असहज करता रहा है। लूला को अस्थिर करने की पूरी कोशिश होगी लेकिन इस बार विश्व का राजनीतिक भूगोल अमेरिका के पक्ष में नहीं दिख रहा है। अमेरिका खुद अपने देश में कई प्रकार की आंतरिक समस्या से जूझ रहा है। संयुक्त राज्य में क्रूर पूंजीवाद के बदले मध्यमार्गी समाजवाद की हवा चल रही है। पूरे लैटिन अमेरिका में लाल तूफान बड़ी तेजी से चल रहा है। अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ चीन व रूस ने तसल्ली से घेरेबंदी की है। भारत जैसे देश दोनों पक्षों से फायदे उठाने के फिराक में हैं। इससे यह साबित होता है कि दुनिया में अब क्रूर पूंजीवाद कमजोर होगा और मध्यमार्गी समाजवाद की तूति बोलेगी। अमेरिका का प्रभाव घटेगा और उसके स्थान पर क्षेत्रीय आर्थिक हितों पर आधारित संगठनों की ताकत बढ़ेगी। ब्रिक्स तथा शंधाई सहयोग संगठन जैसे अर्थिक गठजोड़ों की ताकत भी बढ़ने वाली है। इसलिए भारत को अपनी कूटनीति को भी फिर से मूल्यांकन की जरूरत है।

चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा

शिमला। 8 नवम्बर, 2022 (17 कार्तिक, शक संवत 1944) को पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। हांलाकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था का आरम्भ भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारम्भ हो चुकी होगी। ग्रहण की पूर्णावस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक अवस्था का केवल अंत ही दिखाई देगा।

ग्रहण दक्षिण अमरीका, उत्तर अमरीका, आस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा।

ग्रहण भा.मा.स. अनुसार घं. 14. 39 मि. पर प्रारम्भ होगा जिसकी पूर्णावस्था भा.मा.स. अनुसार घं. 15. 46 मि. पर प्रारम्भ होगी। ग्रहण की पूर्णावस्था का अंत भा.मा.स. अनुसार घं. 17.12 मि. पर होगा तथा आंशिक अवस्था का अंत भा.मा.स. अनुसार घं. 18.19 मि. पर होगा।

देश के पूर्वी भाग में स्थित शहरों यथा कोलकाता एवं गुवाहाटी

में चंद्रोदय के समय ग्रहण की पूर्णावस्था चल रही होगी। कोलकाता में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 20 मिनट की होगी तथा चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 27 मिनट की होगी। गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 38 मिनट की होगी जबकि वहां चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 45 मिनट की होगी।

अन्य शहरों यथा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै एवं बंगलुरू में पूर्णावस्था के अंत के उपरांत चंद्रोदय होगा एवं उस समय आंशिक ग्रहण चल रहा होगा तथा उपयुक्त शहरों में चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि क्रमश: 50 मिनट, 18 मिनट, 40 मिनट एवं 29 मिनट तक की होगी।

भारत में दृश्य अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्तूबर 2023 को घटित होगा जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारत में दृश्य पिछला चंद्र ग्रहण 19 नवम्बर 2021 को घटित हुआ था जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पूर्णतया पृथ्वी की प्रच्छाया से आवृत हो जाता है तथा आंशिक चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा का एक हिस्सा ही पृथ्वी की प्रच्छाया से ढक पाता है।

वन अधिकार कानून को लागू करने को लेकर कोई उल्लेख नही है भाजपा के घोषणा पत्र में

शिमला। हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर, 2022 को आगामी 14वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। बुनियादी सुविधा के मुद्दे, जैसे प्रदेश में, 21% गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं और 12% से ज्यादा लोग बेरोज़गार हैं, चुनावी एजेंडे में अभी भी हैं। आजीविका और कनेक्टिविटी के मुद्दों से जुड़ी हुई है, राज्य में वन अधिकार क़ानून को लागू करने की मांग।

वन अधिकार क़ानून, 2006 में भारतीय संसद में देश के वन आश्रितों की मांग के बाद पारित एक कानून है। देश भर में यह क़ानून जंगलों में और उसके आसपास रहने वाली आबादी की तीन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है ।

1. आजीविका को मजबूत करना और उनका समर्थन करने के लिए

क) कृषि और आवास के लिए कब्जे के तहत वन भूमि के अधिकार की कानूनी मान्यता (13 दिसंबर 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले)

ख) सामुदायिक उपयोग के लिए वन भूमि के अधिकारों की कानूनी मान्यता-जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे, लकड़ी आदि

2. वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत और आसान बनाकर स्थानीय ग्रामीण विकास में मदद-जैसे ग्राम सड़क निर्माण, पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाडी आदि

3. समुदाय को जिम्मेदारी देकर समुदाय आधारित वन संरक्षण और वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार

हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए इस कानून के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पिछले सप्ताह भर में हिमधरा पर्यावरण समूह सहित चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर के अन्य सामुदायिक संगठनों ने साथ मिलकर विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अथवा कांग्रेस, भाजपा, सीपीआईएम और आप पार्टी के कार्यालय में वन अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन को लेकर सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट के अनुसार, 'छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनावों में, वन अधिकार एक प्रमुख मुद्दा रहा था और एफआरए को राजनीतिक दलों ने घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। हिमाचल में जहां भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग वन श्रेणी में है, राज्य की ग्रामीण आबादी को इस कानून से लाभ होगा।

यह क़ानून, केंद्रीय वन कानूनों द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन अधिकारों के प्रावधानों के आधार पर, यह बुनियादी भूमि अधिकार प्रदान करता है, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में और समुदाय आधारित वन संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इतना ही नहीं, विकास के अधिकार के प्रावधान के होने से लगभग 70% वन क्षेत्र वाले ग्रामीण पहाड़ी राज्य में स्थानीय जनकल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। इस प्रावधान के तहत 2012 से 2019 तक 1959 से अधिक जन कल्याण के कार्यो को मंजूरी मिली। मुख्य रूप से ये अनुमतियाँ गाँव की लिंक सड़कों और स्कूलों के लिए मिली। इसी के चलते हम नाचन, सराज, किन्नौर और ठियोग में राजनीतिक उम्मीदवारों को राजनीतिक लाभ उठाते हुए देखा जा सकता है। 'अभी तक राज्य सरकारों ने केवल विकास कार्यो के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए इस कानून को आंशिक रूप से लागू करने में इच्छाशक्ति दिखाई है, लेकिन क़ानून के अन्य प्रावधानों को लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया विशेष रूप से सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को धारा 3(1) के तहत मान्यता मिलने का अधिकार।

अब तक राज्य भर में 3000 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) के दावे दायर किए गए हैं, जिनमें से केवल 129 पटों का आवंटन-चंबा और लाहौल स्पीति में हुआ। और हाल ही में एक अथक जन अभियान के बाद किन्नौर में ऐसे 300 से अधिक व्यक्तिगत मामलों को मंजूरी दी गई। व्यक्तिगत वन अधिकारों का उपयोग दशकों से राजस्व रिकॉर्ड में 'नाजाय कब्जा' के रूप में दर्ज योग्य दावेदारों के अधिकारों का सत्यापन कर क़ानूनी मान्यता देने के लिए किया जा सकता है।

हिमधरा पर्यावरण समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 70 लाख की कुल आबादी में से कम से कम 86% जनता वन अधिकार क़ानून 2006 के तहत संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। राज्य में 55. 9 लाख मतदाताओं (2022 में सूचीबद्ध मतदाता) में से, कम से कम 70% मतदाता इस क़ानून के तहत संभावित दावेदार हैं। राज्य सरकार ने 2016 तक इस कानून के कार्यान्वयन के लिए राजस्व ग्राम स्तर पर 17503 वन अधिकार समितियों (FRCs) का गठन किया। यह कानून दो प्रकार की श्रेणियों -अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों (ओटीएफडी) को अधिकार देता है। हिमाचल में अधिकांश लाभार्थी ओटीएफडी श्रेणी में आते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम एक तिहाई है। यदि हम निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार वितरण को देखें, तो हम पाते हैं कि संभावित एफआरए दावेदार मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से आधे (34) में बड़ी संख्या में (60,000 से 1 लाख के बीच) मौजूद हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन से लेकर सिरमौर जिलों तक फैले हुए हैं।

हिमाचल में इस क़ानून के पारित होने के 15 साल बाद भी यह प्रदेश पूरे देश में इस क़ानून को लागू करने में अन्य राज्यों से पिछड़ा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ दिनों में अपने राजनीतिक घोषणापत्र जारी किए हैं। कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोनों ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य सीमांत समुदायों के कल्याण के लिए वन अधिकार कानून को लागू करने का वादा किया है। हालांकि राज्य की भाजपा सरकार ने, 2018 में इस कानून को मिशन मोड में लागू करने का वादा विधान सभा सत्र के दौरान कहा था, कल अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वन अधिकार क़ानून को लागू करने को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।

निर्वाचन प्रबंधन निकाय सामूहिक कारवाई द्वारा लोकतांत्रिक मानकों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएंगे: निर्वाचन आयुक्त

शिमला। 'निष्पक्ष निर्वाचन' के लिए साझेदारी के अगुआ के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'ईएमबी की भूमिका, प्रारूप और क्षमता' विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह की निर्वाचन आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अध्यक्षता की।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्त पाण्डेय ने कहा कि यद्यपि चुनाव लोकतंत्र की कुंजी हैं, लेकिन निर्वाचन प्रबंधन निकायों (यानी ईएमबी) की चुनाव संपन्न कराने की कार्यात्मक दक्षता की गुणवत्ता उनकी चुनौतियों का समाधान करने और स्वतंत्रता बनाए रखने में कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। उन्होंने समस्त ईएमबी से लोकतांत्रिक मानदंडों व प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने और सामूहिक कारवाई के लिए सभी उपयुक्त मंचों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

निर्वाचन आयुक्त पाण्डेय ने वैश्विक स्तर पर ईएमबी के समक्ष आ रही ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलों द्वारा जनसाधारण को लुभाने के प्रयास, मतदाताओं की उदासीनता जैसी उभरती चुनौतियों को रेखांकित करते हुए इनके समाधान के लिए सुव्यवस्थित तरीके से आपसी सहयोग, निरंतर संबद्धता और नियमित आधार पर जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रबंधन, मतदान प्रबंधन, चुनावी प्रौद्योगिकी, मिथ्या सूचनाओं पर नियंत्रण, फेक न्यूज, साइबर सुरक्षा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने से जुड़े सभी पहलुओं पर वैश्विक मानक और एसओपी तैयार करने की आवश्यकता है।

पाण्डेय ने कहा कि अधिक से अधिक लोकतांत्रिक देशों को साथ लाने का प्रयास इस तरह किया जाना चाहिए कि वे चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के कार्य में शामिल और संलग्न हो सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरूरतमंद ईएमबी को क्षमता निर्माण के लिए अधिक प्रभावी सहायता देने हेतु भागीदार संगठनों की भूमिकाओं को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

पिछले दो दिनों के दौरान, तीन सत्रों में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

'निष्पक्ष निर्वाचन' सुनिश्चित करने के लिए ईएमबी की भूमिका और प्रारूप के संदर्भ में पहला सत्र 'ईएमबी के समक्ष आने वाली वर्तमान चुनौतियां' विषय पर मॉरीशस के निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस सत्र में मैक्सिको, चिली, नेपाल और यूनान के निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश कीं। अध्यक्ष ने सत्र का समापन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए ईएमबी और निर्वाचन प्राधिकरणों द्वारा की गई पहल की सराहना की और कहा कि एक दूसरे की अच्छी पद्धतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

'भविष्य की चुनौतियां' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र की सह-अध्यक्षता सेक्रेटरी जनरल, इंटरनेशनल आइडिया और हेलेनिक गणराज्य, यूनान के निर्वाचन एवं राजनीतिक दलों संबंधी विभाग के प्रमुख, निर्वाचन निदेशालय, आंतरिक मंत्रालय ने की। इस सत्र में ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन आयोग और सीओएमईएलईसी, फिलीपींस के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश कीं। सत्र में कहा गया कि निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और सबसे बढ़कर ईएमबी को अपने मुख्य कार्यो के सुचारु प्रबंधन में लचीलापन लाने की जरूरत है।

आईएफईएस के प्रेजिडेंट और सीईओ ने 'ईएमबी की क्षमता' विषय पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। सत्र में आईएफईएस के कंट्री डायरेक्टर (श्रीलंका और बांग्लादेश), यूएनडीपी के प्रतिनिधि और मतदाता सूची एवं परिणाम विभाग के प्रमुख, निर्वाचन निदेशालय, आंतरिक मंत्रालय, हेलेनिक गणराज्य, यूनान ने प्रस्तुतियां पेश कीं।

आईएफईएस के प्रेजिडेंट और सीईओ ने निष्पक्ष निर्वाचन को सुरक्षित रखने के लिए ताकत और कमजोरियों पर गौर करने तथा एक दूसरे से सीखने के लिए आवश्यक नए परिप्रेक्ष्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईएमबी पर जानबूझकर हमले, गलत सूचना, मिथ्या सूचना सहित खतरों की पहचान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सामाजिक एकजुटता को प्रभावित किए जाने के साथ बहुत कुछ बदल गया है। वक्ताओं ने कहा कि ईएमबी निष्पक्ष निर्वाचन के संरक्षक हैं, इसलिए उनको प्रक्रियाओं के कुशल संचालन से बढ़कर अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस प्रकार ईएमबी की क्षमताओं, अधिकार, जवाबदेही और स्वतंत्रता को तदनुसार नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने श्याम सरन नेगी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की

शिमला/शैल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हिमाचल के गौरव और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री नेगी के लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकाचार और योगदान के प्रति एक दुर्लभ भाव और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजीव कुमार किन्नौर जिले में श्री नेगी के पैतृक गांव कल्पा पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और दिवंगत नेगी को पुष्पांजलि अर्पित की।

दिवंगत नेगी जी की अनुकरणीय भावना और लोकतंत्र में आस्था को नमन करते हुए कुमार ने कहा, 'श्री नेगी 70 सालों से ऊपर लगातार मतदान करते रहे और जाते जाते भी पोस्टल बैलेज द्वारा 2 नवंबर को अपना फर्ज अदा कर गए। श्री नेगी की यह कर्तव्य निष्ठा, युवा मतदाताओं के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। दिवंगत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब देशवासी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोकतंत्र की नींव को और सुदृढ़ करें।' सीईसी ने हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से श्री श्याम सरन नेगी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में 12 नवंबर, 2022 को मतदान करने का आग्रह किया।

सीईसी कुमार ने एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद रखने में योगदान देने के लिए देश भर के 80 साल से अधिक आयु के 1.8 करोड़ और 100 साल से अधिक आयु के 2.5 लाख मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सम्मानित वरिष्ठ नागिरकों के लोकतंत्र में निरंतर भागीदारी से निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी और सुगम चुनाव कराते रहने की जिम्मेदारी का अहसास और बढ़ जाता है।

परिवार के सदस्यों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बातचीत के दौरान श्री नेगी के बेटे ने सीईसी राजीव कुमार द्वारा श्री श्याम सरन नेगी को भेजे गए एक आभार पत्र को याद किया। उन्होंने बताया कि श्री नेगी को पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि वह परिवार के युवाओं को लोकतंत्र के त्यौहार में सक्रिय भागीदारी के लिए वोट डालने को प्रोत्साहित करेंगे। ज्ञात रहे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सीईसी ने देश भर के सभी शताब्दी मतदाताओं के लिए एक आभार पत्र लिखा था।

श्री श्याम सरन नेगी का 106 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के कल्पा निधन हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने श्री श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए आभार जताया।

भाजपा पहले 2017 में लोगों से किये गये वादों का पूरा हिसाब दे :प्रतिमा सिंह

शिमला/शैल। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को कोरा जुमलों का पुलिंदा करार

देते हुए कहा है कि भाजपा को पहले 2017 में लोगों से किये गए वादों का भी पूरा हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जयराम सरकार न तो कर्मचारियों के प्रति सम्वेदनशील ही रही और न ही किसानों, बागवानो व आम लोगों के प्रति। पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की नसीहत देने वाले जयराम आज कर्मचारियों व आम लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रहें है। भाजपा का कोई भी नेता महंगाई व बेरोजगारी पर कभी कोई बात नही करते। अब प्रदेश में सत्ता हाथ से जाते देख भाजपा फिर से लोगों को झूठे सपने दिखा कर अपना राजनैतिक हित साधने का असफल प्रयास कर रही है।

आज इंदौरा में पार्टी प्रत्याशी मालेन्द्र राजन, देहरा के हरिपुर में डॉ. राजेश शर्मा व ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के मजीन में संजय रत्न के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूर्व में किये गये अपने घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नही किया। उन्होंने कहा कि आज अब फिर भाजपा अपने संकल्प पत्र से लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों को भाजपा की जुमलेबाजी के प्रति सचेत करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी स्तर पर न तो खुद गुमराह होना है और न ही अन्य लोगों को गुमराह होने देना है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास जनबल है। उन्होंने कहा कि चार उप चुनाव कांग्रेस इसी जनबल पर जीती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज 74 हजार करोड़ के कर्ज में डूब गया है,जो बहुत ही चिंता की बात है। भाजपा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा का डबल इंजन का दावा पूरी तरह खोखला है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश की ऐसी कोई भी मदद नही की है जिससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होती व बिगड़ती अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होता।

प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती पेपर लीक को भाजपा का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि यह पेपर लीक नही हुआ बल्कि एक साजिश के तहत इसे बेचा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच कर इसके गुनहगारों को सलाखों के पीछे करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। लोगों की भावनाओं से खेलना इसकी आदत है। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वह कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने के लिये अपना पूरा समर्थन कांग्रेस को दे, जिससे प्रदेश में जन भावनाओं को पूरा किया जा सकें।

मायावती 6 नवंबर को बद्दी में करेंगी चुनावी रैली:जसवीर सिंह गढ़ी

शिमला/शैल। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 6 नवंबर को बद्दी में एक विशाल चुनावी रैली करेंगी। गढ़ी ने कहा कि मायावती की रैली की तैयारियों की सारी अहम जिम्मेदारी पंजाब राज्य को दी गई है, जिसके तहत पंजाब के नेतृत्व से गंभीर चर्चा के बाद जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है।

इस मौके पर प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि पंजाब बहुजन समाज पार्टी के कामकाज को देखने वाले पंजाब से बसपा नेतृत्व के 30 बड़े चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, विधायक एवं प्रभारी डॉ. नछतर पाल, प्रदेश प्रभारी अजीत सिंह भैनी, प्रभारी भगवान सिंह चौहान, प्रभारी कुलदीप सिंह सरदुलगढ़, प्रभारी राजा राजिंदर सिंह नन्हेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव मेहरा, गुरमेल चुम्बर, बलविंदर कुमार, लाल चंद औजला, जसवंत रॉय, गुरलाल सेला, ठेकेदार राजिंदर सिंह, परवीन बंगा, गुरनाम चौधरी, जगजीत सिंह छड़बर, राजिंदर रिहाल, दलजीत रॉय, जोगा सिंह पनौंडीआ, बलविंदर बिट्टा, मीना रानी, जसवंत रॉय, कुलवंत सिंह महतों, चमकौर सिंह वीर, भाग सिंह सरिह, हरभजन सिंह दुलमा, डॉ. जसप्रीत सिंह बीजा, अधिवक्ता शिव कल्याण जी, कुल 30 चेहरों का चयन किया गया। बेनीवाल ने कहा कि साहिब कांशी रामजी के जाने के बाद प्रदेश पजाब से बाहर, आयोजित होने वाली रैली की व्यवस्थाओं में बसपा पंजाब यूनिट को मुख्य जिम्मेदारी दी है कि वह बड़ा सामाजिक और आर्थिक योगदान दें। बेनीवाल ने कहा कि पंजाब के नेतृत्व को दी गई यह महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी यह दर्शाती है कि देश के राष्ट्रीय नेतृत्व में पंजाब के कार्यकर्ताओं के मजबूत माने जाने लगे हैं, जो पिछले 20 वर्षो में पहली बार हुआ है। 20 साल पहले, जबकि साहिब कांशीराम जी के जाने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने हमेशा पंजाब के लिए विशेष योगदान दिया है, यहां तक कि राज्य मुख्यालय भी 2004 में केवल बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से अस्तित्व में आया था।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 20176 लीटर शराब जब्त की

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के अंतर्गत विभागीय कार्यबल पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के विरुद्ध निरंतर कारवाई कर रहा है। आबकारी लाइसेंसियों के परिसरों एवं गोदामों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार जारी किये गए लाइसेंस में वर्णित शर्तों की अनियमितता पाये जाने पर भी सख्त कारवाई की जा रही है।

यूनुस ने कहा कि जिला बिलासपुर मे कार्यबल द्वारा लाइसेंस परिसर का निरीक्षण किया गया और यहां पर लाइसेंस की वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान कार्यबल ने 850 पेटी (10200 बोतलें) को अपने कब्ज़े में लेकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कार्यबल द्वारा राजस्व जिला बद्दी मे लाईसेंसी के विरुद्ध कारवाई करते हुए 840 पेटी(10080 बोतलें)को अपने कब्ज़े में लिया है क्योंकि लाईसेंसी द्वारा आबकारी घोषणाओं में वर्णित शर्तो की उल्लंघना की गई थी।

उन्होंने कहा कि जिला ऊना में भी लाईसेंसी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई की गई है। कार्यबल ने परिसर का निरीक्षण किया तथा अनियमितता पाये जाने पर परिसर में रखे 435 पेटी(5220 बोतलें) को कब्ज़े में लेकर स्टॉक को सील कर दिया है।

आयुक्त ने कहा कि लाईसेंसी द्वारा लाइसेंस में वर्णित शर्तो के अनुसार बिक्री एवं भण्डारण न करने के कारण जिला मण्डी में भी कार्यबल ने कारवाई करते हुए 113 पेटी (1356 बोतलें) को कब्ज़े में लेकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में भी कारवाई करते हुए कार्यबल ने 955 लीटर अवैध कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए मौके पर नष्ट किया।

यूनुस ने बताया कि प्रदेश में आदर्श चुनाव संहिता लागू है और कार्यबल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों एवं भीतरी भागों मे शराब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर विभाग कड़ी नज़र रख रहा है और सूचना मिलने पर इनके विरुद्ध कारवाई की जा रही है। प्रदेश में नाका लगाकर वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। विभागीय अधिकारी 24/7अपने कार्य क्षेत्रों में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं।

कांगड़ा में 8–9 को पैराग्लाइडिंग और ड्रोन फ्लाइंग पर प्रतिबंध

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर को प्रस्तावित कांगड़ा जिले के दौरे के दृष्टिगत जिले में पैराग्लाईडिंग, ड्रोन, हॉट एयर बैलून इत्यादि की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 8 नवम्बर शाम 5 बजे से 9 नवम्बर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री दौरे को लकेर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

कांगेंस ने की भाजपा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश के मुख्यमंत्री के आई टी मैनेजर किशोर शर्मा के खिलाफ मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल व ह्यूमन राइट्स के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने अलग-अलग शिकायत में नड्डा का कांग्रेस पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय व उन्हें वोट के लिये इस्तेमाल करने के आरोप को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि नड्डा अपने भाषणों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए समाज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया है। इसलिए उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत में हमीरपुर के बड़सर में लोगों की धार्मिक भावनाओं के उकसाने का आरोप लगाया है उनका भाषण पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है ।

मुख्यमंत्री के आई टी मैनेजर किशोर शर्मा पर चुनावों के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जिसमें सरकारी कार्यालय से भाजपा के आईटी सेल को चलाना और सरकारी गाड़ी के दुरपयोग का आरोप है।

छात्रों के लिए योग, ध्यान और हैप्पीनेस को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगा नौणी विवि

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी छात्रों के लिए योग, ध्यान और हैप्पीनेस को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने के लिए हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट (एचईटी), हैदराबाद के साथ साझेदारी कर रहा है। यह सहयोग एचईटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है।

नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से आईसीएआर द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कौशल विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक पाठयक्रम के पुनर्गठन में हमारी मदद करेगा। एचईटी और आईसीएआर के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। इस एमओयू में एक भागीदार के रूप में, यह सर्वोत्तम आधुनिक प्रथाओं के साथ स्थिरता और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके छात्रों को बहुत लाभान्वित करेगा।

उन्होंने कहा कि एमओयू के तहत यूएचएफ विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के लिए योग और ध्यान में फाउंडेशन कोर्स शुरू करेगा। तनाव को कम करने में प्रशिक्षण से छात्रों को उनके जॉब में बहुत लाभ होगा। प्रो. चंदेल ने कहा कि माडयूल में मानवता, रिश्तों, भौतिक जीवन को संतुलित करने के तरीके, पेशे या व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण और विनम्रता का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, एचईटी और यूएचएफ प्राकृतिक खेती पर अपने अपने स्तर पर अग्रणी काम कर रहे हैं और विभिन्न फसलों को एकीकृत करते हुए अलग-अलग मॉडल विकसित किए हैं, इसलिए दोनों संगठन किसान समुदाय के लाभ के लिए इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान गतिविधियों करेंगे। छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान से छात्रों और शिक्षकों को एक-दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी।

एचईटी द्वारा विकसित किए जाने वाले पाठयक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप पर्यावरणीय स्थिरता और टिकाऊ प्रौद्योगिकी में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। एमओयू के तहत विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ।

27 नवम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन

शिमला/शैल। लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा की सचिव विजय लक्ष्मी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिले में मुकद्दमों के त्वरित और शांतिपूर्ण निवारण के लिए 27 नवम्बर 2022 को ऑनलाईन लोक अदालतों का आयोजन जिले के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के मामले, आवश्यक सेवाओं संबंधित मामले, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों से संबंधित केस लगाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत और ट्रैफिक चालान तथा अन्य छोटे अपराध के लिए लोक अदालत का ऑनलाईन आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अपने मुकद्दमों को 27 नवम्बर 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें जिससे उनका सुलभ और शीघ्र समाधान हो सके।

भाजपा का घोषणा पत्र जुमला, पांच साल पहले किए वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपीः सुक्खू

शिमला/शैल। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला करार दिया है। कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने पांच साल पहले

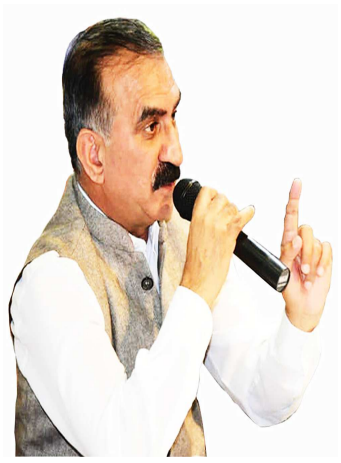

किए प्रदेश की जनता से बड़े वादे किए थे, लेकिन इन अपने वादों को जयराम सरकार ने पूरा नहीं किया। अब चुनावों में अपनी हार को देख भाजपा फिर से नए वादे लेकर भाजपा आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में जो घोषणाएं की है वो हवा हवाई हैं। ये घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरने वाली नहीं है। उन्होंने बेजीपी को जुमलेबाजी पार्टी बताया।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रही है वह खोखली है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33 फीसदी आरक्षण नौकरियों में देने का वादा किया है, इससे पहले बीजेपी ने 2017 के घोषणाएं पत्र में पुलिस विभाग में होने वाली कांस्टेबल भर्ती में भी 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को देने का वादा किया था जो कि बेजीपी सरकार ने पूरा नहीं किया। इस तरह गुमराह करने का काम बीजेपी ने किया है। अब फिर से आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है। जब पहले का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है तो इस वादे पर कैसे महिलाएं भरोसा करेगी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में मंहगाई चरम पर है। महिलाएं इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। खाने की वस्तुओं के दाम आसामान छू रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर कुछ नहीं किया, उल्टे गैस, तेल के दाम बढाकर लोगों पर बोझ डालने का काम किया। बेजीपी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन तो दे दिए लेकिन गैस के दाम जो पहले मनमोहन सरकार के समय 450 रुपए थे उनको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। बेजीपी ने बीपीएल महिलाओं को साल में तीन सिलेंडर फ्री देने की बात की है, लेकिन क्या एक परिवार पूरे साल में तीन ही सिलेंडर चलाता है। बाकी सिलेंडर के लिए गरीब महिलाएं कहां से पैसा लाएंगी। अगर बीजेपी इस योजना को लागू कर भी देती है तो इसके इसमें बीपीएल की महिलाएं ही कवर होंगी वो भी उनको तीन सिलेंडर मिलेंगे, बाकी निम्न मध्यमवर्गीय परिवार कहां से गैस के लिए पैसे लाएगा।

सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और बागवानों के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं की है। भाजपा सरकार शुरू से ही किसानों और बागवानों के साथ घोर अन्याय करती आई है। बेजीपी कह रही है कि सेब में इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर 18 फीसदी जीसीटी का छह फीसदी वह वहन करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने कार्टन पर जीएसटी क्यूं थोपा है। बीजेपी सरकार बनने पर छह फीसदी जीएसटी खुद वहन कर इसकी सब्सिडी देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सेब सीजन में बागवानों के रोष और बढ़ते दवाब को देखते हुए जयराम सरकार ने पहले भी छः फीसदी सब्सिडी कार्टन पर देने की बात की. मगर सेब बागवानों को अपनी जेब से कार्टन का पूरा रेट देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार एंटी हेल नेट की सालों से पेंडिंग सब्सिडी को रिलीज नहीं कर पा रही है और अब फिर छह फीसदी जीएसटी की सब्सिडी देने का शगूफा छेड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर बेजीपी किसानों और बागवानों की उतनी हितैशी है तो मोदी सरकार कार्टन पर लगे जीएसटी को बिल्कुल खत्म करे।

उन्होंने बीजेपी को किसान बागवान विरोधी देते हुए कहा कि बीजेपी ने खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली खाद, दवाइयों की सब्सिडी खत्म कर इनके दाम दो से तीन गुना बढ़ाए गए हैं, इससे सेब, अन्य फलों और अन्य फसलों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेहतर होता कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में खाद और दवाइयों पर सब्सिडी देने का वादा करती। घोषणापत्र में किसानों और बागवानों के हित्तों के प्रति बीजीपी की संवेदनहीनता नजर आ रही है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल के कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तक नही दिया। हिमचाल में 7 फीसदी मंहगाई भत्ता कर्मचारियों का पेंडिंग पड़ा है। खुद पांच सालों में जयराम सरकार ने जमकर फिजूल खर्ची की और कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कर्मचारियों को ओ पी एस तो दूर इसकी मांग करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कर्मचारियों को यहां तक कहा कि अगर उनको पेंशन चाहिए तो वह चुनाव लड़े। इसके विपरीत कांग्रेस ने ओपीसी का वादा किया है और इसको कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा।

सुक्खू ने बेजीपी की सरकार ने पांच सालों में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। रिक्त पदों को भरने की कोई जहमत नहीं उठाई और बड़ी संख्या में खाली पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया। हालात यह रही कि करूणामूलक बेरोजगारों को एक साल से अधिक समय तक अनशन करना पड़ा और इसके बाद चुनाव घोषित होने पर उनको मजबूरन अपना अनशन समाप्त करना पड़ा। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता बेजीपी की बातों में आने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा को पूरा जवाब देगी और उसको सता से बेदखल करगी।

न विजन और न ही वजनः सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न विजन और न ही वजन, यह केवल प्रलोभन का पुलिंदा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का न सिर है न सिरा, यह मैनिफेस्टो आधारहीन एवं कोरी घोषणा है। काँग्रेस विजन लेस, थिंक लेस और डायरेक्शन लेस पार्टी है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस पर मुहर लगाता है।

उन्होंने कहा महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण का आलाप गाने वाले इनके होनहार नेता अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को स्थान देना भूल गये।

कांग्रेस ने 2012 के अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगा था और इस बार महिलाओं की बारी है।

कांग्रेस नेताओं के प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देना, क्या काँग्रेस इसको महिला सशक्तिकरण का आधार समझती है?

कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काकर, उनके कंधों पर बंदूक रख चुनावी गोली चलाने का काम कांग्रेस कर रही है, काँग्रेस भूल गई की यह हिमाचल के कर्मठ, संघर्षशील एवं प्रगतिशील कर्मचारी है, जो राज्य निर्माण में भाजपा के साथ खड़े हैं।

कांग्रेस ये बताएं की जो वादे उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता से किया थे क्या वो पूरे किये? राजस्थान में बड़ी-बड़ी बातें की किया कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में वादों का पहाड़ खड़ा किया हुआ कुछ नहीं। हिमाचल में झूठ का किला बना रहे 12 नवंबर को यह भरभरा कर गिरने वाला है।

हिमाचल में झूठ का किला 12 नवंबर को एक बार फिर भरभरा कर गिरने वाला है।

एक बार फिर काँग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गैरेंटियाँ दे रही है, पहले तो काँग्रेस के नेता यह बता दें की इन गैरेंटियों को पूरा करने के लिए काँग्रेस के नेता कहाँ से 60 हजार करोड़ रुपये लेकर आएंगे?

कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं से झूठे वादे किये हैं, महिलाओं को प्रति माह 1,500 मानदेय । इस योजना के

तहत सालाना 3306 करोड़ रुपये एवं 5 साल में 16,530 करोड़ रुपए की राशि का खर्चा आएगा, काँग्रेस के नेता यह बताएं की आखिर इस योजना के लिए बजट कहाँ से आएगा?

एक तरफ काँग्रेस के नेता रेवड़ियों की तरह गारंटीयां बाँट रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के सीनियर नेता आनंद शर्मा मीडिया में बयान देते हैं की उनको पता ही नहीं की काँग्रेस द्वारा दी गई गारंटीयों को लेकर पैसा कहाँ से आएगा?

यह सिर्फ वादों का मायाजाल है जिसमें कांग्रेस प्रदेश की भोली भाली जनता को फाँसना चाहती है।

ऐसे कोरे और हास्यप्रद वादे जनता से किये गए हैं, जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं ।

कांग्रेस की घोषणाओं में क्या देंगे? कितना देंगे? कैसे देंगे? यह स्पष्टता नजर नहीं आती और पलटने में इनका स्टाइक रेट बहुत जायद है तो प्रदेश की जनता को इनसे बचकर रहना चाहिए।

कांग्रेस का पिछले चुनाव का बकाया अभी बाकी है जनता इस चुनाव में उसका हिसाब करेगी।

आबकारी विभाग ने 53594 लीटर कच्ची शराब जब्त की

शिमला/शैल। आबकारी विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों

में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में अलग-अलग जिलों में भारी मात्रा में शराब को कब्जे में लिया है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत शराब की बिक्री, भंडारण को लेकर विभाग सख्त कारवाई कर रहा है। शराब की दुकानों एवं थोक विक्रेताओं के परिसरों में निरीक्षण करते हुए 7,901 शराब की पेटियां कब्जे में ली गई हैं जिनकी कीमत लगभग 3.12 करोड़ है। उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम एवं अन्य नियमों की उल्लंघना में मंडी, ऊना, नूरपुर, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा में यह कार्रवाई की गई है।

यूनुस ने कहा कि अवैध तथा कच्ची शराब के खिलाफ अभियान में पिछले 24 घण्टों में टीमों ने प्रदेश में 53,594 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया है तथा दोषियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का वितरण न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी एवं कार्यबल टीमें अपने परिधि इलाकों में सजगता से अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ संयुक्त नाके लगा कर शराब के अवैध कारोबार पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद से आज तक प्रदेश में लगभग 5,26,303.475 लीटर शराब बरामद की गई है जिसकी कीमत लगभग 7,16,93,504 रुपये है। शराब की किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के बारे में टोल फी नंबर 1800-180-8062, ईमेल vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नम्बर 9418611339 पर शिकायत कर सकते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की पूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियां व्यवहार्य समाधान हैं

शिमला/शैल। नन्द लाल शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने शिमला में पंप स्टोरेज-अवसर एवं चुनौतियाँ सहित ऊर्जा भंडारण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। शर्मा केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी),

सोसाइटी ऑफ पावर इंजीनियर्स, इंडिया एंड एफ्रो एशियन रिजन द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मंच, शिमला, इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया के सहयोग से आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, नन्द लाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा भंडारण प्रणालियां डीकार्बोनाइज्ड ऊर्जा मिश्रण की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन के सहायतार्थ व्यवहार्य समाधान हैं। पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध भंडारण ऊर्जा के सबसे बड़े रूपों में से एक है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा दक्षता है।

एसजेवीएन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में, एसजेवीएन का कुल पोर्टफोलियो लगभग 42,000 मेगावाट है, जिसमें अखिल भारतीय विद्युत मंत्रालय द्वारा चिन्हित 12,610 मेगावाट की 10 पंप स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर सीबीआईपी के सचिव ए.के.दिनकर, सीईआरसी के पूर्व सदस्य ए.एस.बख्शी, एचपीएसईबी के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल, इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), हि.प्र. चैप्टर, शिमला के अध्यक्ष विश्व मोहन जोशी, एमएसईटीसीएल के सदस्य/निदेशक(प्रचा.) अनिल कोलप और सीबीआईपी के निदेशक संजीव सिंह भी उपस्थित रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

10, अप्रैल 1999 को पुरानी पैन्शन के स्थान पर नई पैन्शन योजना लागू करने का एम ओ यू साईन हुआ था

शिमला/शैल। आज हिमाचल ही नहीं वरन देश के उन 21 राज्यों के कर्मचारी पुरानी पैन्शन योजना पुन: बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे बहाल भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब पंजाब में इसे बहाल करने का फैसला कर लिया है। हिमाचल के चुनावों में कांग्रेस ने दस गारंटियों में इसे पहला स्थान दिया है और सरकार बनने पर मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में इसे लागू करने का वायदा भी कर दिया है। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर अभी भी असमंजस में चल रही है। बल्कि कुछ कर्मचारी नेता पुरानी पैन्शन योजना खत्म करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इस समय यह मुद्दा केन्द्रिय मुद्दा बन चुका है। इसलिये पूरे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इसे जनता के बीच रखा जाना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इसके प्रभाव दुरगामी होंगे। स्मरणीय है कि 1999 में प्रदेश में भी और केन्द्र में भी भाजपा की सरकारें थी। बल्कि केंद्र में तेरह दिन तेरह महीनों के बाद मार्च 1999 में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी और इस सरकार में अरुण शोरी के अधीन पहली बार देश को विनिवेश मंत्रालय देखने को मिला था। यह विनिवेश मंत्रालय भाजपा का एक नीतिगत फैसला था। स्वभाविक था कि जब भी इस फैसले के तहत सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश को घटाया जाता तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता। इसलिये केन्द्र ने सभी विशेष श्रेणी राज्यों सहित 21 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया जिसकी हर शर्त कर्मचारियों को प्रभावित करती थी। उस समय कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे साइन करने से मना भी कर दिया था। लेकिन हिमाचल की भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर पायी।

2003 में जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गयी तब यह मुद्दा फिर उठा क्योंकि 1999 में हुये एमओयू को ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। तब वीरभद्र सरकार ने मई 2004 में बड़े प्रयत्नों से केंद्र के साथ एक नया एमओयू साइन करके पुराने में कुछ संशोधन करवाये। इन संशोधनों के बाद भाजपा ने अपने ऊपर लग रहे कर्मचारियों की पैन्शन खत्म करने के आरोप को कांग्रेस के नाम लगाना शुरू कर दिया। विधानसभा के अन्दर इस पर भारी हंगामा हुआ था। तब सरकार ने इन समझौता ज्ञापनों का सच जनता के सामने रखा। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दिसम्बर 2004 में **"समझौता ज्ञापन तथ्य क्या है ?"** नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की थी। इस पुस्तिका में सारे तथ्य दर्ज हैं। अप्रैल 1999 में क्या साईन हुआ था। मार्च 2004 में क्या साईन हुआ था। दोनों ज्ञापन इसमें दर्ज हैं। इनको पढ़े बिना यह आरोप लगाना सही नहीं होगा की कौन सी सरकार कर्मचारियों की हितैशी रही है। आज शायद राजनेता और कर्मचारी नेता दोनों को ही इस समझौता ज्ञापन की जानकारी नहीं है। इसलिये इस समझौता ज्ञापन का दस्तावेज पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप अपनी राय बना सकें।

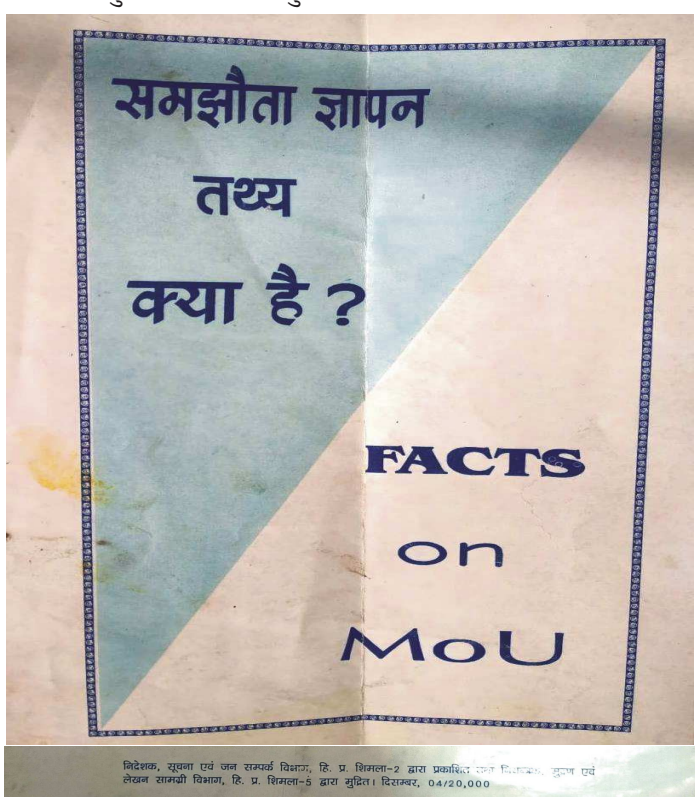

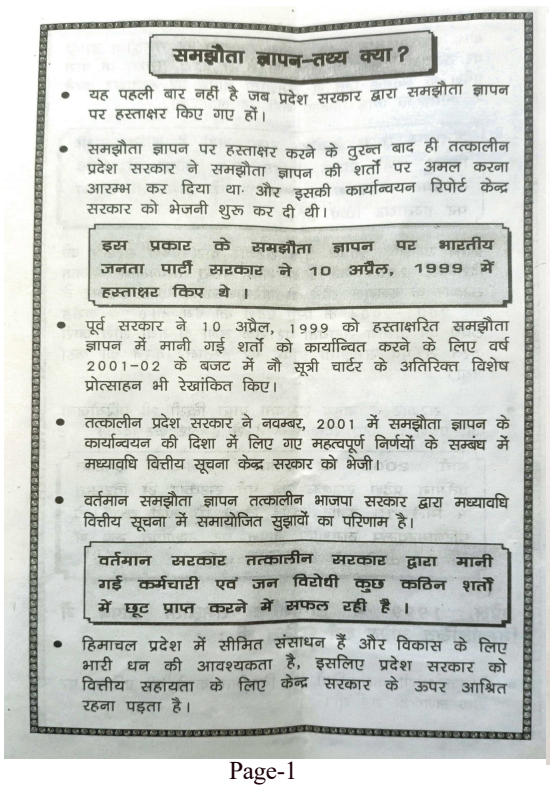
समझौता ज्ञापन-तथ्य क्या ?

- यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हों।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद ही तत्कालीन प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन की शर्तों पर अमल करना आरम्भ कर दिया था· और इसकी कार्यान्वयन रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजनी शुरू कर दी थी।

इस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 अप्रैल, 1999 में हस्ताक्षर किए थे ।

- पूर्व सरकार ने 10 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में मानी गई शर्तों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में नौ सूत्री चार्टर के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भी रेखांकित किए।
- तत्कालीन प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2001 में समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बंध में मध्यावधि वित्तीय सूचना केन्द्र सरकार को भेजी।
- वर्तमान समझौता ज्ञापन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा मध्यावधि वित्तीय सूचना में समायोजित सुझावों का परिणाम है।

वर्तमान सरकार तत्कालीन सरकार द्वारा मानी गई कर्मचारी एवं जन विरोधी कुछ कठिन शर्तों में छूट प्राप्त करने में सफल रही है ।

- हिमाचल प्रदेश में सीमित संसाधन हैं और विकास के लिए भारी धन की आवश्यकता है, इसलिए प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है।

Page-1

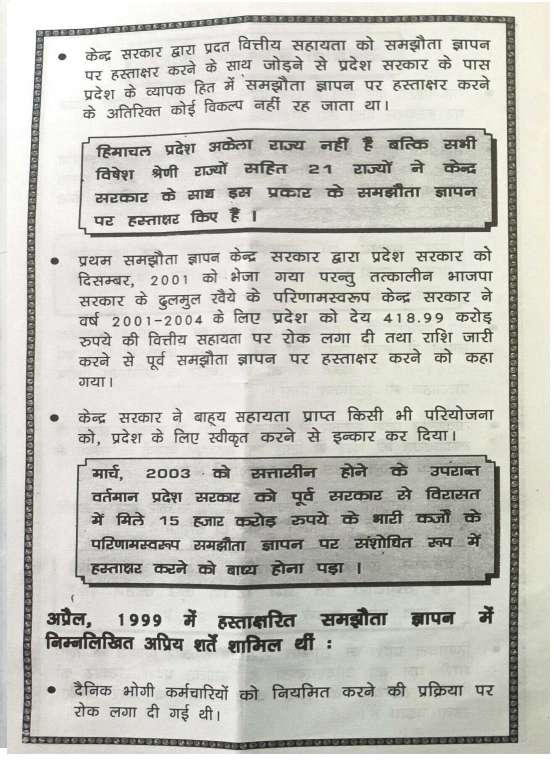
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ जोड़ने से प्रदेश सरकार के पास प्रदेश के व्यापक हित में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता था।

हिमाचल प्रदेश अकेला राज्य नहीं है बल्कि सभी विशेष श्रेणी राज्यों सहित 21 राज्यों ने केन्द्र सरकार के साथ इस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

- प्रथम समझौता ज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को दिसम्बर, 2001 को भेजा गया परन्तु तत्कालीन भाजपा सरकार के दुलमुल रवैये के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-2004 के लिए प्रदेश को देय 418.99 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी तथा राशि जारी करने से पूर्व समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया।
- केन्द्र सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त किसी भी परियोजना को, प्रदेश के लिए स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया।

मार्च, 2003 को सत्तासीन होने के उपरान्त वर्तमान प्रदेश सरकार को पूर्व सरकार से विरासत में मिले 15 हजार करोड़ रुपये के भारी कर्जों के परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन पर संशोधित रूप में हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ा ।

अप्रैल, 1999 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित अप्रिय शर्तें शामिल थीं :

- दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

Page -2

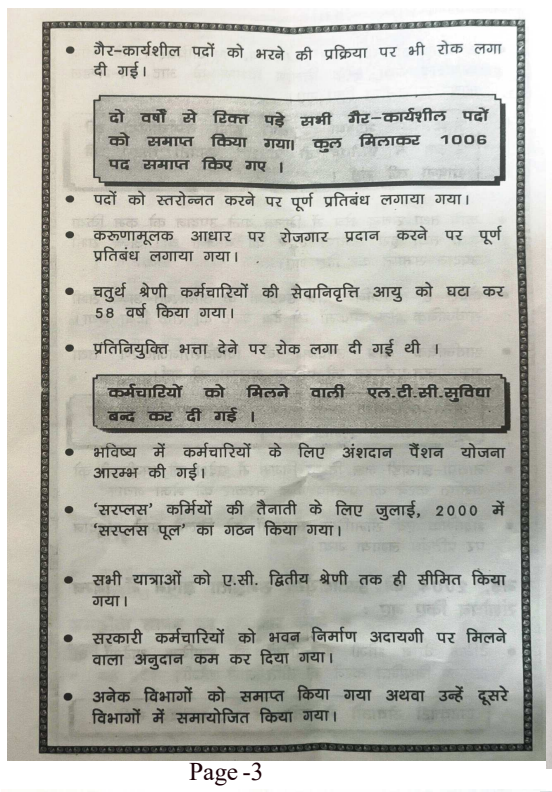
- गैर-कार्यशील पदों को भरने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई।

दो वर्षों से रिक्त पड़े सभी गैर-कार्यशील पदों को समाप्त किया गया। कुल मिलाकर 1006 पद समाप्त किए गए ।

- पदों को स्तरोन्नत करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को घटा कर 58 वर्ष किया गया।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता देने पर रोक लगा दी गई थी ।

कर्मचारियों को मिलने वाली एल.टी.सी.सुविधा बन्द कर दी गई ।

- भविष्य में कर्मचारियों के लिए अंशदान पैंशन योजना आरम्भ की गई।
- 'सरप्लस' कर्मियों की तैनाती के लिए जुलाई, 2000 में 'सरप्लस पूल' का गठन किया गया।
- सभी यात्राओं को ए.सी. द्वितीय श्रेणी तक ही सीमित किया गया।
- सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अदायगी पर मिलने वाला अनुदान कम कर दिया गया।
- अनेक विभागों को समाप्त किया गया अथवा उन्हें दूसरे विभागों में समायोजित किया गया।

Page -3

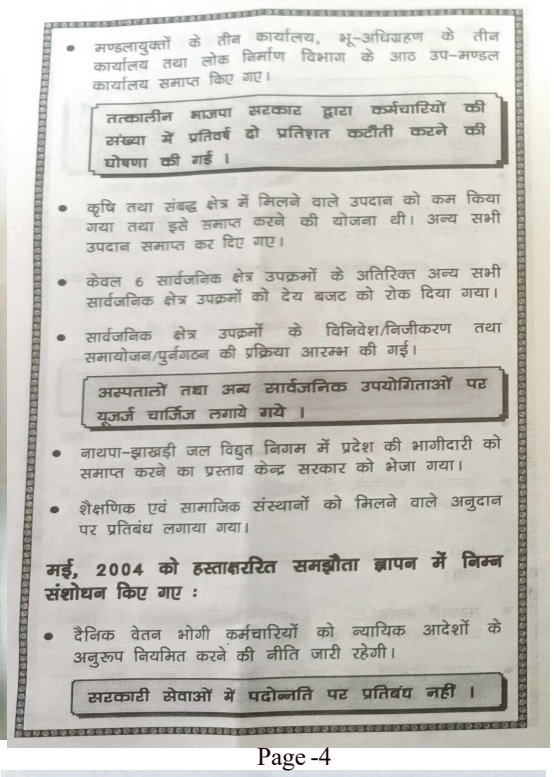
- मण्डलायुक्तों के तीन कार्यालय, भू-अधिग्रहण के तीन कार्यालय तथा लोक निर्माण विभाग के आठ उप-मण्डल कार्यालय समाप्त किए गए।

तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की गई ।

- कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में मिलने वाले उपदान को कम किया गया तथा इसे समाप्त करने की योजना थी। अन्य सभी उपदान समाप्त कर दिए गए।
- केवल 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बजट को रोक दिया गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश/निजीकरण तथा समायोजन/पुर्नगठन की प्रक्रिया आरम्भ की गई।

अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं पर यूजर्ज चार्जिज लगाये गये ।

- नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत निगम में प्रदेश की भागीदारी को समाप्त करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया।
- शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों को मिलने वाले अनुदान पर प्रतिबंध लगाया गया।

मई, 2004 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्न संशोधन किए गए :

- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यायिक आदेशों के अनुरूप नियमित करने की नीति जारी रहेगी।

सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर प्रतिबंध नहीं ।

Page -4

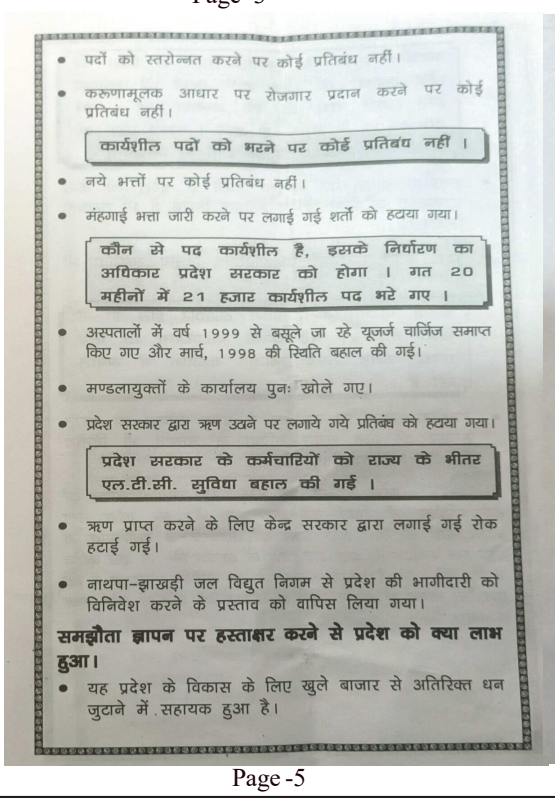
- पदों को स्तरोन्नत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं।

कार्यशील पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

- नये भत्तों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- मंहगाई भत्ता जारी करने पर लगाई गई शर्तों को हटाया गया।

कौन से पद कार्यशील है, इसके निर्धारण का अधिकार प्रदेश सरकार को होगा । गत 20 महीनों में 21 हजार कार्यशील पद भरे गए ।

- अस्पतालों में वर्ष 1999 से बसूले जा रहे यूजर्ज चार्जिज समाप्त किए गए और मार्च, 1998 की स्थिति बहाल की गई।
- मण्डलायुक्तों के कार्यालय पुनः खोले गए।
- प्रदेश सरकार द्वारा ऋण उठाने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया गया।

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को राज्य के भीतर एल.टी.सी. सुविधा बहाल की गई ।

- ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटाई गई।
- नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत निगम से प्रदेश की भागीदारी को विनिवेश करने के प्रस्ताव को वापिस लिया गया।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से प्रदेश को क्या लाभ हुआ।

- यह प्रदेश के विकास के लिए खुले बाजार से अतिरिक्त धन जुटाने में सहायक हुआ है।

Page -5

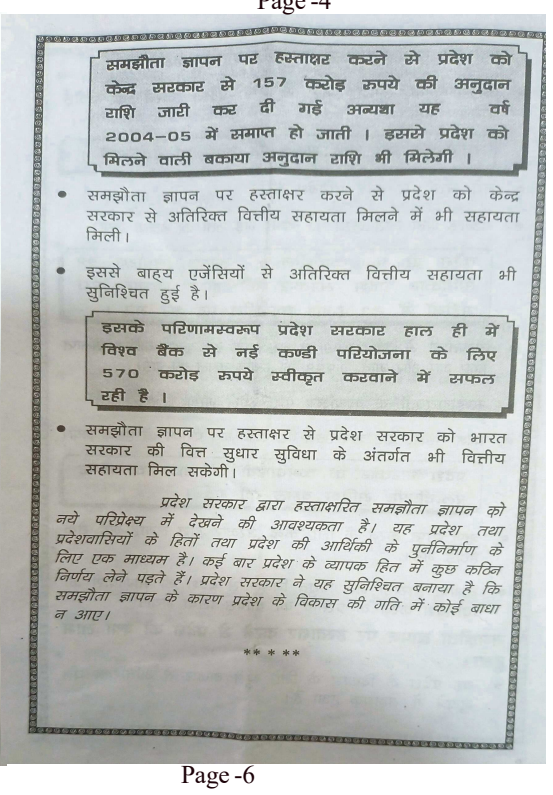
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से प्रदेश को केन्द्र सरकार से 157 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर दी गई अन्यथा यह वर्ष 2004-05 में समाप्त हो जाती । इससे प्रदेश को मिलने वाली बकाया अनुदान राशि भी मिलेगी ।

- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से प्रदेश को केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने में भी सहायता मिली।
- इससे बाह्य एजेंसियों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी सुनिश्चित हुई है।

इसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार हाल ही में विश्व बैंक से नई कण्डी पटियोजना के लिए 570 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाने में सफल रही है ।

- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से प्रदेश सरकार को भारत सरकार की वित्त सुधार सुविधा के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को नये परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। यह प्रदेश तथा प्रदेशवासियों के हितों तथा प्रदेश की आर्थिकी के पुर्ननिर्माण के लिए एक माध्यम है। कई बार प्रदेश के व्यापक हित में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि समझौता ज्ञापन के कारण प्रदेश के विकास की गति में कोई बाधा न आए।

****

Page -6